

झारखंड राज्यविद्युत बोर्ड और अन्य

बनाम

मैसर्स लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कॉ. पी. लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील सं. 2909/2014)

फरवरी 28,2014

[के. एस. राधाकृष्णन और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

विद्युत कानून:

टैरिफ निर्धारण की शक्ति-आयोजित: विशेष रूप से स्थानांतरित किया गयाएस. ई. आर. सी. और राज्य विद्युत बोर्ड की पूरी तरह से निंदा की जाती है। यह शक्ति-बिजली अधिनियम, 2003 के आने से पहले, बिजली अधिनियम, 1910 और उसके बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 लागू थे- यह संबंधित राज्यों में विद्युत बोर्ड था जो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहे थे और संचालन दरों का निर्धारण कर रहे थे। जिस पर बिजली की आपूर्ति की जानी थी-बिजली अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, शुल्क तय करने की शक्ति एस. ई. आर. सी. को दी गई है- 2003 अधिनियम ने दूरी बना ली है शुल्क विनियमन सहित सभी प्रकार के नियमों से सरकार, जो अब विशेष रूप से एस. ई. आर. सी. को सौंपा गया है, इस प्रकार, राज्य विद्युत बोर्डों के पास शुल्क तय करने की

कोई शक्ति नहीं है जो एस. ई. आर. सी.के विशेष अधिकार के तहत है -विद्युत अधिनियम, 2003 -विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948।

एस. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क का निर्धारण- एच. टी. उपभोक्ताओं से मांग शुल्क का मुद्दा- माना गया-1994 के एच. टी. समझौते को विद्युत अधिनियम, 2003 और शुल्क संरचना के तहत संरक्षित नहीं किया गया था-एच. टी. उपभोक्ताओं से मांग शुल्क के मुद्दे पर विचार किया गया और टैरिफ आदेश दिनांकित 27.12.2003 में इसे प्रभावी किया गया है, जो 1.1.2004 से प्रभावी हुआ।

विलम्ब/विलंब: रिट याचिकाएँ दाखिल करने में देरी- 2004 के शुल्क क बाद भी, 1994 एच. टी. समझौते के खंड 4 (सी) के आधार पर जे.एस.ई.बी. द्वारा उठाये गये बिल अनुसूची-कनेक्शन काटने की धमकी के तहत किया गया भुगतान-रिट याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पहले की अवधि के बिलों के तहत ली गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश -इस आधार पर चुनौती दी गई कि उपभोक्ताओं द्वारा रिट याचिका दाखिल करने में देरी हुई-माना गया: विलम्ब को विधिवत समझाया गया -उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काटने की धमकी के विरोध में जे. एस. ई. बी. द्वारा जारी की गई बिलों की राशि का भुगतान किया था- ऐसा करते समय, उन्होंने जे. एस. ई. बी. के समक्ष विशेष दलील रखी थी कि अब उसे 2004

शुल्क अनुसूची के अनुसार बिल जारी करना चाहिए- बात नीचे ही रह गईजे. एस. ई. बी. के स्तर पर विचार किया गया, जो 2004 शुल्क अनुसूची के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय के साथ-साथ एस.ई.आर.सी का दरवाजा खटखटाता रहा।

वर्ष 1994 में,बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी. के हित में पूर्ववर्ती) और उपभोक्तों के बीच एच. टी. समझौता किया गया था, जिसमें अन्तर अलावा, जे.एस.ई.बी. के द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्तों से वसुले जाने वाले शुल्क को निर्धारित किया गया था । समझौते के 4 (सी) में न्यूनतम गारंटी शुल्क का प्रावधान था। वर्ष 2003 में, विद्युत अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के तहत शुल्क तय करने की शक्ति थी एस. ई. आर. सी. को दिया था।एस. ई. आर. सी. ने नया शुल्क तय करने का आदेश पारित किया, विद्युत अधिनियम की धारा 86 के तहत अनुसूची (2004 टैरिफ अनुसूची)। उपभोक्ता- प्रतिवादी की शिकायत यह भी कि जे. एस. ई. बी. ने समझौते में निर्दिष्ट खंड 4 (सी)के अनुसार बिल भेजना जारी रखा, जिसका उपभोक्ताओं द्वारा विरोध के तहत भुगतान किया गया। मई 2010 में, उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों को इस आधार पर रद्द करने के लिए रिट याचिकाएं दायर की गई थी कि यह समझौते के खंड 4 (सी) के अनुसार गलत तरीके से बनाया गया था, जिसके कारण 2004 के शुल्क के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।एस. ई. आर. सी. द्वारा अनुसूची। हालांकि,जे. एस. ई. बी. ने तर्क दियाकि

उपभोक्ताओं के साथ किया गया एच. टी. समझौता अभी भी बचा हुआ है क्योंकि 2004 की टैरिफ अनुसूची ने इसे बचा लिया है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

तत्काल अपीलों में, विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे: क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद, जो 10.06.2003 को लागू हुआ और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 27.12.2003 को नया शुल्क आदेश पारित होने के बाद (एस. ई. आर. सी.) 2003 के अधिनियम के अनुसार, राज्य विद्युत बोर्डअभी भी अपने द्वारा निर्धारित शुल्क ले सकते हैं; क्या एच. टी. एस. 1 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मांग शुल्क के मुद्दे को एस. ई. आर. सी. द्वारा दिनांक 27.12.2003 के शुल्क आदेश में गैर विचारणीय छोड़ दिया गया है ताकि इसे राज्य में मौजूदा तरीके से जारी रखा जा सके। दिनांक 27.12.2003 के शुल्क आदेश पर विचार किया गया और उसे प्रभावित किया गया जो 1.1.2004 से लागू हुआ; विद्युत अधिनियम, 2003 से पहले बोर्ड और उपभोक्ता पर किए गए एच. टी. आपूर्ति समझौते पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 ¼ निरसन और बचत खंड) का क्या प्रभाव होगा।

अपीलों को खारिज करना; न्यायालय

अभिनिर्धारित:

1. पुनःविद्युत अधिनियम 2003 के तहत एस. ई. आर. सी. की शक्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और उसके बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 पारित किया गया। यहसंबंधित राज्य में बिजली बोर्ड था जो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा था और संचालन दरों का निर्धारण कर रहा जिस पर बिजली की आपूर्ति की जानी थी। अधिनियम, 1948 की धारा 49 ने बोर्ड को ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्तिको बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार दिया, जैसा की बोर्ड उचित समझता है और समय-समय पर ऐसी आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है और इस उद्देश्य के लिए समान शुल्क तय करने का अधिकार दिया गया था। आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 49 (1) के तहत शुल्क तय करने की इस शक्तिन्यूनतम गारंटी शुल्क तय करने की शक्ति भी शामिल थी। बिहार राज्य में, ऐसी दरें 1993 के शुल्क में तय की गई थीं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ एच. टी. उपभोक्ताओं के लिए शुल्क का प्रावधान किया गया है। एच.टी. की तीन श्रेणियां वहाँ उपभोक्ताओं का उल्लेख किया गया था। एचटीएस-1, II और III तत्काल दोनों तत्काल अपीलों में उपभोक्ताओं को एचटी-1 में रखा गया था। बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच दिनांक 26.4.1994 को एच. टी. समझौता हुआ। इस अनुबंध के खंड 4 के अनुसार, उपभोक्ताओं को भुगतान करना था इस प्रकार आपूर्ति की गई और पंजीकृत या ली गई ऊर्जा के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित और समय-समय पर लागू टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए लागू उचित दरों पर आपूर्ति की गई है। यह

की श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम अनुबंध मांग के अधीन था। आपूर्ति श्रेणी जिसमें उपभोक्ताओं ने महसूस किया। खंड 4 (बी) में बताया गया है कि प्रत्येक माह के लिए उपभोक्ता की अधिकतम मांग किलोवोल्टएम्पीयर (के. वी. ए.) की सबसे बड़ी कुल मात्रा होगी जो उपभोक्ताओं को महीनों में लगातार 30 मिनट के दौरान आपूर्ति के बिंदु पर वितरित किया गया था। खंड 4 (सी) के अनुसार, जे. एस. ई. बी. अनुबंध मांग के 75 प्रतिशत के आधार पर ऊर्जा बिल बढ़ा रहा था। [पैरा 6] [463-एफ-एच; 464-ए-जी]

1.2. विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद, टैरिफ तय करने की शक्ति एस. ई. आर. सी. को दिया गया था। यह शक्ति अधिनियम के तहत एस. ई. आर. सी. को वैधानिक रूप से प्रदान किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से पहले, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत झारखंड एस. ई. आर. सी. का गठन झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। इसके कार्य और कर्तव्य सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अधिसूचित किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003, के पारित होने पर, विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही, अधिनियम 2003 ने 1998 के अधिनियम के तहत गठित एस. ई. आर. सी. एस. को मान्यता दी। एस. ई. आर. सी. द्वारा बनाई गई 2004 टैरिफ अनुसूची, अधिनियम की धारा 86

(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। अधिनियम, 2003 बिजली से संबंधित सभी मामलों पर एक विस्तृत संहिता है जो राज्य विद्युत बोर्डों को अलग-अलग हिस्सों में "अनबंडल" करने का भी प्रावधान करता है।

उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए उपयोगिताएँ। इसके अलावा, नियामक व्यवस्था एस. ई. आर. सी. को सौंपी गई है, जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यह अधिनियमसरकार को टैरिफ विनियमन सहित सभी प्रकार के विनियम से दूर कर दिया है, जो अबविशेष रूप से एस. ई. आर. सी. को सौंपा गया। इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि राज्य विद्युत बोर्डों के पास टैरिफ तय करने की कोई शक्ति नहीं है जो एस. ई. आर. सी. के विशेष डोमेन के अन्तर्गत है। इस कानूननी स्थिति को न्यायिक मान्यता प्राप्त है [पैरा 7 से 10] [464-जी-एच; 465-ए-सी और एफ; 467-डी]

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2010) 4 एस.सी.सी. 603; 2010 (3) एस.सी.आर. 609; गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड (2008) 4 एस. सी. सी. 755; 2008 (4) एस.सी.आर. 822; ए. पी. ट्रांस्को बनाम साई रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड (2011) 11 एस. सी. सी. 34; 2010 (8) एस. सी. आर. 636-पर निर्भर।

2. पुनः क्या दिनांक 26.4.1994 का समझौता 2004 टैरिफ अनुसूची के द्वारा सहेजा गया है ?

2.1. जब जे.एस.ई.बी ने एस. ई. आर. सी. के अनुरोध पर टैरिफ तय किया। जे.एस.ई.बी ने स्वयं जब इसउद्देश्य के लिए एस. ई. आर. सी. से संपर्क किया।एस. ई. आर. सी. के समक्ष जे. एस. ई. बी. द्वारा दायर टैरिफ याचिका में, जे. एस. ई. बी. ने अनुबंध की मांग के 75 प्रतिशत के तरीके को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं दिया और एस. ई. आर. सी. ने 140-के.वी. माह शुल्क की अनुमति दी। टैरिफ आदेश में अनुलग्नक 5.1 जिसमें 'टैरिफ अनुसूची' शामिल है। यह टैरिफ अनुसूची, जो टैरिफ प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, राज्य पर भी बाध्यकारी है। हालाँकि, जे. एस. ई. बी. ने स्वयं एस. ई. आर. सी. के लिए अपने आवेदन/संदर्भ में कोई भी न्यूनतम गारंटी शुल्क तय करना तय करने के लिए नहीं कहा था। जे. एस. ई. बी. ने 2003-04 के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए एस. ई. आर. सी. के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रस्ताव, में एच. टी. एस. (उच्च तनाव सेवा) उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियाँ सहित सभी उपभोक्ताओं के सम्बंध में मौजूदा टैरिफ और इसके द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दोनों का संकेत दिया। एस. ई. आर. सी. ने आवश्यक कार्यवाही करने के बाद सभी श्रेणियों का टैरिफ तय कर दिया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तावित टैरिफ एच. टी. एस.-1. उपभोक्ताओं के लिए एक बोर्ड 2004 टैरिफ अनुसूची की सारणी 5.28 और 5.29 में पुनः प्रस्तुत किया गया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के पहलू पर एस.ई.आर.सी. द्वारा विधिवत विचार किया गया था।[पैरा 12,13] [469-सी-एफ; 470-जी-एच: 471-ए]

2.2 टैरिफ आदेश से यह भी पता चला कि एस. ई. आर. सी. यहां तक की जे. एस. ई. बी. के प्रस्ताव की तुलना टैरिफ से भी कर दी थी। भारत के अन्य राज्यों में प्रचलित और उसके विस्तृत विवरण के बाद, इसने एच. टी. एस. उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को मंजूरी दी, जिसका उल्लेख 2004 के शुल्क की तालिका 5.31 में किया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एस. ई. आर. सी. न्यूनतम गारंटी शुल्क से संबंधित खण्ड से अनभिज्ञ था, जो जे. एस. ई. बी. अपने उपभोक्ताओं से उनके साथ किये गये पहले के समझौते के अनुसार वसूल रहा था । स्थिति 2004 टैरिफ अनुसूची में चर्चा से स्पष्ट हो जाएगी जिसमें एस. सी. आर. सी. ने एच.टी.एस. उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को संशोधित करने और अनुमोदित करने के विशिष्ट कारण दिए थे। उच्च न्यायालय ने सही माना कि एस. ई. आर. सी. ने मांग शुल्क और जिस तरीके से इसे चार्ज किया जायेगा, इसके दावे के सम्बंध में बिजली बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। बोर्ड खंड 5.1 की सहायता नहीं ले सकता, जहाँ यह देखा गया कि कुछ मामलों का निपटा नहीं गया है और वे वैसे ही बने रहेंगे जैसे वे राज्य

में अस्तित्व में थे, क्योंकि मांग शुल्क के लिए जली बोर्ड द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही जिस तरीके से इसे लिया जाएगा और इस प्रस्ताव पर एस. ई. आर. सी. द्वारा विचार किया गया और इसके बाद शुल्क आदेश जारी किया गया है। जे. एस. ई. बी. ने एस. ई. आर. सी. के समक्ष स्पष्टीकरण आवेदन भी दायर किए गए थे जिसमें तर्क दिया गया था कि एच. टी.-1 उपभोक्ताओं के साथ समझौता के खंड 4 (सी) को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम मांग शुल्क समझौते के खंड 4 (सी) के तहत निर्धारित किए जाएंगे। ये थे आवेदन एस. ई. आर. सी. द्वारा विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया। जे. एस. ई. बी. द्वारा उन आदेशों को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं की गई थी।

इसलिए, जे. एस. ई. बी. के लिए अब बहस करने में बहुत देर हो चुकी है कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के इस पहलू को एस. ई. आर. सी. द्वारा 2004 की टैरिफ अनुसूची में नहीं निपटा गया था [पैरा 14 से 16] [473-सी-डी; 475-जी-एच; 476-ए-ई]

3. पुनः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 का प्रभाव।

इस अवधि के दौरान लागू टैरिफ 2003-04 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश दिनांकित 27.12.2003, जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कानून का बल। इस प्रकार, भले ही यह इस आधार पर मान लिया जाए कि पहले किये गये वैधानिक समझौते थे, बचाये जाने पर, विचाराधीन समझौता

2004 टैरिफ अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। यहां तक की विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 पर आधारित तर्कभी इस मामले के परिणामों में कोई बदलाव नहीं लाएगा।

उच्च न्यायालय के जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई उसमें कोई गलती नहीं थी

[पारस 19,20] [479-एफ-जी; 481-ए-बी]

पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह 1955 (1) एससीआर 893;बीएसईएस बनाम। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (2004) 1 एस. सी. सी. 195: 2003 (4) पूरक एस. सी. आर. 932-पर निर्भर।

4. यह प्रस्तुत किया गया था कि रिट याचिकाएं दाखिल करने में देरी हुई थी क्योंकि 1994 समझौते के खंड 4 (सी) के आधार पर जे. एस. ई. बी. द्वारा जारी किये गये बिल, 2004 की टैरिफ अनुसूची के निर्माण के बाद भी उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जा रहा था और उन्होंने वर्ष 2010 में रिट याचिकाएं दायर करके न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ऐसे परिदृश्य में, उच्च न्यायालय को कम से कम अपीलार्थी को पहले की अवधि के लिए उठाए गए बिलों के तहत दी गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था और यह उनके साथ अन्याय होगा जो उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता से राशि की वसुली करेंगे। जहां तक रिट याचिका दायर करने में देरी का सवाल है, घटनाओं के घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता

है कि इसकी विधिवत व्याख्या की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कनेक्शन काटने की धमकी के विरोध में उपभोक्ताओं ने जे. एस. ई. बी. द्वारा बढ़ाये गए बिलों की राशि का भुगतान किया था।

ऐसा करते समय, उन्होंने जे. एस. ई. बी. के समक्ष विशिष्ट दलील रखी थी जे. एस. ई. बी. ने कहा कि उसे अब 2004 टैरिफ अनुसूची के अनुसार बिल जारी करना चाहिए। यह मामला जे.एस. ई. बी. के स्तर पर विचाराधीन रहा, जो 2004 टैरिफ अनुसूची के स्पष्टीकरण की मांग के लिए न्यायालय के साथ-साथ एस. ई. आर. सी. का दरवाजा खटखटया। स्पष्टीकरण आवेदन किए गए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था एस. ई. आर. सी. हालाँकि, चूंकि जे. एस. ई. बी. ने इन आवेदनों को खारिज करने के बाद भी अपने रुख पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए उपभोक्ताओं ने अदालत का रुख किया और रिट दायर की। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय तक पहुँचने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी को अन्यायपूर्ण और संवर्धन की दलील उपलब्ध नहीं होगा। सर्वप्रथम, ऐसी कोई याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के समक्ष समक्ष नहीं उठाई गई थी। विशेष अनुमति याचिका में, अपीलों की सुनवाई के समय, पहली बार यह निवेदन किया गया था। इसके अलावा, यह एक मामला नहीं है कर का भुगतान जो उपभोक्ता पर एक बोझ है। पैरा 21 से 23] [481-बी-एच; 482-ए-बी]

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (2013) 12 स्केल 397; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब नाम. भारत संघ (1997) 5 एस. सी. सी. 536-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ:

2010 (3) एससीआर 609 उस पर भरोसा करें पैरा 9

2008 (4) एससीआर 822 उस पर भरोसा करें पैरा 10

2010 (8) एससीआर 636 उस पर भरोसा करें पैरा 10

(2013) 12 स्केल 397 संदर्भित किया गया है पैरा 17

1955 (1) एससीआर 893 उस पर भरोसा करें पैरा 17

2003 (4) पूरक। एस. सी. आर. 932 पर निर्भर पैरा 19

(1997) 5 एस. सी. सी. 536 संदर्भित किया गया पैरा 23

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2909/2014

सिविल अपील सं. 2910, 2911 और 2913/2014 में उच्च न्यायालय के 05.07.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के साथ

अजीत कुमार सिन्हा, एमएल वर्मा, एमएस मित्तल और एके गांगुली, ऐश्वर्या सिन्हा, अम्भोज कुमार सिन्हा, हिमांशु शेखर, फैसल खान, एमपी

झा राम एकबाल रॉय, हर्षवर्द्धन झा, दिलीप पिल्लई, कौशिक पोद्दार, शंकर लाल अग्रवाल, देवाशीष भरुका, जसमीत कुआर अपीलकर्ता की ओर से चंदन कुमार राय और रविन दुबे;

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, जे. द्वारा दिया गया था

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. अनुमति दी गई.

3. दोनों मामलों में अपीलकर्ता झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) है, जो दो अपीलों में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 जुलाई 2011 के सामान्य निर्णय से व्यथित है। ये अपीलें अपीलकर्ता जेएसईबी द्वारा दो रिट याचिकाओं में उस अदालत के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17 फरवरी 2010 के आदेशों के खिलाफ दायर की गई थीं, जो मेसर्स द्वारा दायर की गई थीं। लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड और मैसर्स. लक्ष्मी इस्पात उद्योग (प्रत्येक अपील में प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में सूचीबद्ध और इसके बाद 'उपभोक्ता' के रूप में संदर्भित)। इन प्रतिवादियों ने उन रिट याचिकाओं में जेएसईबी द्वारा उठाए गए बिलों की वैधता पर सवाल उठाया था, मुख्य रूप से इस आधार पर कि बिल झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद "एसईआरसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित टैरिफ के विपरीत और उससे अधिक थे। ")।

उनके तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की डिवीजन बेंच ने भी पुष्टि की है।

4. इसमें शामिल विवाद की एक झलक देने के लिए, वर्ष 1994 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी के हित में पूर्ववर्ती) और उपभोक्ताओं के बीच एचटी समझौता किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क निर्धारित किया गया था, जिसे वसूला जाना था। जेएसईबी द्वारा इन उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं से जेएसईबी। समझौते के खंड 4(सी) में न्यूनतम गारंटी शुल्क का प्रावधान था। वर्ष 2003 में विद्युत अधिनियम बनाया गया। निस्संदेह, इस अधिनियम के तहत टैरिफ तय करने की शक्ति एसईआरसी को दी गई है। एसईआरसी ने बिजली अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 86 के तहत नई टैरिफ अनुसूची (संक्षेप में '2004 टैरिफ अनुसूची') तैयार करने का आदेश पारित किया। हालाँकि, जेएसईबी ने समझौते में उल्लिखित खंड 4 (सी) के अनुसार बिल भेजना जारी रखा, जिसका उपभोक्ताओं ने विरोध के तहत भुगतान किया। मई 2010 में, उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बिलों को इस आधार पर रद्द करने के लिए रिट याचिकाएं दायर की गईं कि यह समझौते के खंड 4 (सी) के अनुसार गलत तरीके से बढ़ाया गया था, जिसका 2004 टैरिफ अनुसूची के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एसईआरसी द्वारा. हालाँकि, जेएसईबी ने तर्क दिया कि

उपभोक्ताओं के साथ किया गया एचटी समझौता अभी भी बचा हुआ है क्योंकि 2004 टैरिफ अनुसूची इस समझौते को बचाती है।

5. चूंकि उपभोक्ताओं की रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को डिवीजन बेंच ने पहले ही बरकरार रखा है, यह स्पष्ट है कि जेएसईबी द्वारा उठाई गई याचिकाओं को उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला है। हमारे सामने भी वही विवाद उठे थे जो जेएसईबी ने हाई कोर्ट में उठाए थे। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 (बी) के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 185 (2) (ए) भी पहले के अधिनियम के पिछले संचालन की स्पष्ट रूप से रक्षा करती है, जो उसके तहत विधिवत किया या बचाया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे निम्नलिखित हैं:

(i) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद, जो 10.6.2003 को लागू हुआ और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 27.12.2003 को नए टैरिफ आदेश पारित होने के बाद, 2003 के अधिनियम के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड क्या आप अभी भी अपने द्वारा निर्धारित टैरिफ चार्ज करते हैं?

(ii) क्या एचटीएस-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं को डिमांड चार्ज का मुद्दा राज्य आयोग द्वारा दिनांक 27.12.2003 के टैरिफ आदेश में गैर-विचारणीय छोड़ दिया गया है ताकि इसे राज्य में मौजूद तरीके से जारी रखा जा सके या नहीं दिनांक 27.12.2003 के टैरिफ आदेश में इस पर विचार किया गया है और इसे प्रभावित किया गया है जो 1.1.2004 से लागू हुआ?

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 से पहले बोर्ड और उपभोक्ता पर किए गए एचटी आपूर्ति समझौते पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 (निरसन और बचत खंड) का क्या प्रभाव होगा?

6. इन सवालों से निपटने के दौरान, हम आगे के मौलिक तथ्यों और दोनों पक्षों के विद्वान वकील की विस्तृत दलीलों का वर्णन करेंगे।

1. पुनः विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एसईआरसी की शक्ति।

2003 के अधिनियम में निहित कानूनी स्थिति शायद ही विवाद में हो। वर्ष 2003 में इस अधिनियम के लागू होने से पहले, हमारे पास भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 था और उसके बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 पारित किया गया था। यह संबंधित राज्यों में बिजली बोर्ड है जो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा था और संचालन दरों का निर्धारण कर रहा था जिस पर बिजली की आपूर्ति की जानी थी। अधिनियम, 1948 की धारा 49 ने बोर्ड को ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार दिया, जैसा कि

बोर्ड उचित समझता है और समय-समय पर ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए बनाया जाता है और इस उद्देश्य के लिए एक समान टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 49(1) के तहत टैरिफ तय करने की इस शक्ति में न्यूनतम गारंटी शुल्क तय करने की शक्ति भी शामिल थी। बिहार राज्य में ऐसी दरें वर्ष 1993 के टैरिफ में तय की गई थीं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ एचटी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का प्रावधान किया गया है। वहां एचटी उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां बताई गईं। एचटीएस-I, II और III. तत्काल अपील में दोनों उपभोक्ताओं को एचटी-आई श्रेणी में रखा गया था। बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच दिनांक 26.4.1974 को एचटी समझौता किया गया। इस अनुबंध के खंड 4 के अनुसार, उपभोक्ताओं को बोर्ड द्वारा निर्धारित और समय से लागू टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं पर लागू उचित दरों पर आपूर्ति की गई और पंजीकृत या ली गई ऊर्जा के लिए बोर्ड को भुगतान करना था। समय पर। यह आपूर्ति श्रेणी की उस श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम अनुबंध मांग के अधीन था जिसमें उपभोक्ता आते थे। खंड 4(बी) में बताया गया है कि प्रत्येक माह के लिए उपभोक्ता की अधिकतम मांग किलोवोल्ट एम्पीयर (केवीए) की सबसे बड़ी कुल मात्रा होगी जो उपभोक्ताओं को महीनों में लगातार 30 मिनट के दौरान आपूर्ति के बिंदु पर वितरित की गई थी। चूंकि जेएसईबी ने क्लॉज 4 (सी) के अनुसार शुल्कों पर काम

किया है, जिसकी वह मांग कर रहा है, हम नीचे उक्त क्लॉज को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

4(सी) किसी भी महीने में आपूर्ति के लिए अधिकतम मांग शुल्क महीने की अधिकतम केवीए मांग या अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर आधारित होगा, खंड 13 के प्रावधान के अधीन। पहले बारह महीने की सेवा के लिए अधिकतम हालाँकि, किसी भी महीने के लिए मांग शुल्क उस महीने की वास्तविक मासिक अधिकतम मांग पर आधारित होगा।

इस प्रकार, उपरोक्त खंड के अनुसार, जेएसईबी अनुबंध मांग के 75% के आधार पर ऊर्जा बिल बढ़ा रहा था।

7. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिजली अधिनियम, 2003 लागू होने के बाद, टैरिफ तय करने की शक्ति एसईआरसी को दी गई है। यह शक्ति अधिनियम के तहत एसईआरसी को वैधानिक रूप से प्रदान की गई है। हालाँकि, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या के तहत किया गया था। 1763 दिनांक 22 अगस्त

2002। इसके कार्यों और कर्तव्यों को सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अधिसूचित किया गया था।

8. विद्युत अधिनियम, 2003 के पारित होने पर, विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, अधिनियम 2003, 1998 अधिनियम के तहत गठित एसईआरसी को मान्यता देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य खंड इस प्रकार है:

बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने, बिजली के युक्तिकरण के लिए एक अधिनियम टैरिफ, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए।

9. यह भी विवाद में नहीं है कि एसईआरसी द्वारा बनाई गई 2004 टैरिफ अनुसूची अधिनियम की धारा 86 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही है। में पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय विद्युत

विनियामक आयोग तृ. सचिव., इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि अधिनियम, 2003 बिजली से संबंधित सभी मामलों पर एक विस्तृत कोड है जो उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को अलग-अलग उपयोगिताओं में "अनबंडलिंग" करने का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा, नियामक व्यवस्था राज्य विद्युत नियामक आयोगों को सौंपी गई है, जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस अधिनियम ने सरकार को टैरिफ विनियमन सहित सभी प्रकार के विनियमों से दूर कर दिया है, जो अब विशेष रूप से एसईआरसी को सौंपा गया है। इस अधिनियम की योजना को रेखांकित करने वाली प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैंः.

2003 अधिनियम को बिजली से संबंधित सभी मामलों पर एक विस्तृत संहिता के रूप में अधिनियमित किया गया है। यह उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए एसईबी को अलग-अलग उपयोगिताओं में विभाजित करने का प्रावधान करता है। यह विद्युत अधिनियम, 1910: विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरस्त करता है। 2003 अधिनियम, इसे आगे बढ़ाने में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 अधिनियम) के तहत परिकल्पित नीति ने एक स्वतंत्र और पारदर्शी नियामक तंत्र की स्थापना को अनिवार्य किया है, और नियामक आयोगों को व्यापक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जबकि 1998 अधिनियम क्षेत्र में स्वतंत्र विनियमन

प्रदान करता है टैरिफ निर्धारण का: 2003 अधिनियम ने सरकार को सभी प्रकार के विनियमन, अर्थात् लाइसेंसिंग, टैरिफ विनियमन, ग्रिड कोड निर्दिष्ट करना, खुली पहुंच के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की सुविधा आदि से दूर कर दिया है। "[पैराग्राफ 17]

2003 के अधिनियम में आयोग द्वारा दोहरे कार्यों के निष्पादन के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। धारा 61 केंद्रीय आयोग द्वारा विनियम तैयार करने के लिए सक्षम प्रावधान है: टैरिफ के नियमों और शर्तों का निर्धारण अधिनियम की धारा 61 के तहत नियामक आयोगों के डोमेन पर छोड़ दिया गया है, जबकि नियामक आयोगों द्वारा वास्तविक टैरिफ निर्धारण शामिल है। अधिनियम की धारा 62 द्वारा. वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। टैरिफ के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करना एक ऐसा कार्य है जो किसी वितरण लाइसेंसधारी को उत्पादन कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति या बिजली के पारेषण या व्हीलिंग के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक टैरिफ निर्धारण से अलग और अलग है। बिजली या बिजली की खुदरा बिक्री के लिए।

26. "टैरिफ" शब्द 2003 अधिनियम में परिभाषित नहीं है। "टैरिफ" शब्द के दायरे में न केवल दरों का निर्धारण बल्कि इससे संबंधित नियम और विनियम भी शामिल हैं। यदि कोई 2003 अधिनियम की धारा

62 के साथ धारा 61 को पढ़ता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक टैरिफ का निर्धारण करेगा, जिसमें नियम और शर्तें भी शामिल हैं जो उपयुक्त आयोग द्वारा धारा के तहत निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 61. 2003 अधिनियम के तहत, यदि कोई धारा 62 को धारा 64 के साथ पढ़ता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मूल्य निर्धारण की तरह टैरिफ निर्धारण प्रकृति में विधायी है, अधिनियम के तहत इसे धारा 111 के माध्यम से लागू किया जाता है। ये प्रावधान, अर्थात् धारा 61, 62 हैं और 64 नियामक आयोगों द्वारा निष्पादित कार्यों की दोहरी प्रकृति को दर्शाते हैं। निर्णय लेना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट करना। [पैराग्राफ 25,26]

(जोर दिया गया)

10. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि राज्य बिजली बोर्डों के पास टैरिफ तय करने की कोई शक्ति नहीं है जो कि आयोग के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत है। इस कानूनी स्थिति को न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है। [देखना गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड, और ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड और अन्य बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्रा. लिमिटेड और अन्य आदि आदि,

11. उपरोक्त कानूनी स्थिति के बावजूद, जेएसईबी का तर्क है कि वर्ष 1994 में उपभोक्ताओं के साथ किया गया समझौता बरकरार है और जेएसईबी को इसके खंड 4 (सी) के अनुसार टैरिफ वसूलने का अधिकार है। जेएसईबी के अनुसार यह स्थिति इस कारण से है कि एसईआरसी द्वारा बनाई गई 2004 टैरिफ अनुसूची का खंड 1.4 ऐसी स्थिति प्रदान करता है और इसके अलावा अधिनियम 2003 की धारा 186 भी इस समझौते को बचाती है। इन दोनों पहलुओं पर, हम पहले ही ऊपर प्रश्न संख्या 2 और 3 तैयार कर चुके हैं और अब उनसे निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे।

2. पुनः क्या दिनांक 26.4.1994 का समझौता 2004 टैरिफ अनुसूची द्वारा सहेजा गया है? जेएसईबी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि 2004 टैरिफ अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो 26.4.1994 के समझौते में विशेष रूप से खंड 4 (सी) में निहित है और टैरिफ अनुसूची ऊर्जा बिलों में इसकी अनुपस्थिति है। 75% अनुबंध के आधार पर उठाई गई मांग को बचा लिया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 26.4.1994 का समझौता एक वैधानिक समझौता है क्योंकि यह 1948 के अधिनियम के तहत था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि यह उपभोक्ताओं का मामला कभी नहीं था कि उपरोक्त प्रावधान को निरस्त, अस्वीकार या नष्ट कर दिया गया था। ऐसा भी नहीं हुआ है। इस प्रयोजन के लिए, श्री सिन्हा ने उपभोक्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दिए गए कथनों पर भरोसा करने की कोशिश की और इस आधार पर यह तर्क दिया

गया कि उपभोक्ताओं ने भी स्वीकार किया कि अनुबंध की मांग का 75% का प्रावधान अनुपस्थित है और 2004 में प्रदान नहीं किया गया था। टैरिफ अनुसूची. उन्होंने एसईआरसी की 2004 टैरिफ अनुसूची के खंड 1.4 पर भी मजबूत भरोसा जताया, जो इस प्रकार है:

मीटर किराया, कम वोल्टेज पर आपूर्ति, कैपेसिटर चार्ज, बिजली शुल्क, छूट, सुरक्षा जमा, अनुबंध मांग से अधिक के लिए अधिभार आदि के संबंध में अन्य सभी नियम और शर्तें राज्य में मौजूदा के समान ही रहेंगी।

इसके अलावा, टैरिफ आदेश 2003-04, खंड 5 में टैरिफ संरचना के डिजाइन और टैरिफ के विश्लेषण शीर्षक के तहत, विशेष रूप से खंड 5.4 में दो भाग टैरिफ संरचना और न्यूनतम गारंटी शुल्क से निपटा गया है जिसमें यह कहा गया था कि "आदर्श रूप से, निर्धारित /मांग शुल्क सिस्टम पर व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा रखी गई मांग के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उपभोक्ता की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली को डिजाइन करने में उपयोगिता की सुविधा प्रदान करता है और इसलिए यह एक न्यायसंगत और उचित तंत्र है। सिस्टम की निश्चित लागतों की वसूली के लिए।

श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया कि हाई टेंशन एग्रीमेंट दिनांक 26.8.2004 का खंड 4(सी) जिस पर प्रतिवादी उपभोक्ता ने 1.1.2004 के काफी बाद बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जब टैरिफ आदेश 2003-04 प्रभावी हुआ, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि इसके बाद बिजली आपूर्ति शुरू होने पर, प्रतिवादी पहले 12 महीनों में वास्तविक खपत के आधार पर केवीए/अधिकतम मांग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके बाद अनुबंध मांग के 75% या दर्ज मांग के आधार पर, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह समान रूप से स्थित सभी एचटीएस-1 उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है।

12. इस तर्क की सराहना करने के लिए, हमें एसईआरसी द्वारा तैयार किए गए 2004 टैरिफ अनुसूची के प्रासंगिक प्रावधान को समझना होगा। यह देखना उचित होगा कि एसईआरसी ने जेएसईबी के अनुरोध पर ही टैरिफ तय किया था जब उसने इस उद्देश्य के लिए एसईआरसी से संपर्क किया था। हमने पाया कि जेएसईबी द्वारा एसईआरसी के समक्ष दायर टैरिफ याचिका में, जेएसईबी ने अनुबंध की मांग के 75% के तरीके को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं दिया और एसईआरसी ने 140-केवी-माह की मांग शुल्क की अनुमति दी। टैरिफ आदेश का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे अलग-अलग खंडों में विभाजित किया गया है, खंड 1. 'परिचय', खंड 2 वह अध्याय है जिसमें 'एआरआर' यानी बोर्ड द्वारा

प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ प्रस्ताव, अनुभाग शामिल है। 3 अध्याय है जिसमें हितधारकों से प्राप्त 'आपतियां' शामिल हैं, धारा 4 वह अध्याय है जिसमें 'एआरआर पर आयोग का विश्लेषण' है, धारा 5 वह अध्याय है जिसमें 'टैरिफ संरचना का डिजाइन और टैरिफ का विश्लेषण' है, धारा 6 वह अध्याय है जिसमें 'टैरिफ संरचना का डिजाइन और टैरिफ का विश्लेषण' शामिल है। 'जेएसईबी को दिशा-निर्देश' और अंत में अनुलग्नक 5.1 है जिसमें 'टैरिफ अनुसूची' शामिल है। यह टैरिफ अनुसूची, जो टैरिफ प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, राज्य पर भी बाध्यकारी है। टैरिफ आदेश के अनुलग्नक 5.1 का प्रासंगिक भाग जिसमें राज्य आयोग ने उच्च तनाव सेवा (एचटीएस) उपभोक्ताओं यानी प्रतिवादी संख्या 1 पर लागू श्रेणी पर टैरिफ प्रयोज्यता से निपटा है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

श्रेणी: उच्च तनाव सेवा (एचटीएस)

1. प्रयोज्यता

100 केवीए से अधिक अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए

2. सेवा का चरित्र

50 चक्र, 6.6 पर 3 चरण। केवी/11 केवी/33 केवी या 132 केवी।

3. टैरिफ

एचटीएस के लिए टैरिफ

विवरण	टैरिफ
रू/केवी/माह	मांग शुल्क
एच.टी.एस.	140
	उर्जा प्रभार
किलोवाट/माह	रू/किलोवाट
सारी खपत	4.00
	मासिक न्यूनतम शुल्क
11 और 33 केवी पर आपूर्ति के लिए	रू250/केवीए
132 केवी पर आपूर्ति के लिए	रू400/केवीए

13. हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जेएसईबी ने स्वयं एसईआरसी को अपने आवेदन/संदर्भ में कोई न्यूनतम गारंटी शुल्क तय करने के लिए नहीं कहा था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जेएसईबी ने नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत 2003-04 के लिए टैरिफ निर्धारण के अपने प्रस्ताव में, एचटीएस की सभी श्रेणियों सहित सभी उपभोक्ताओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ और उसके द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दोनों का संकेत दिया था। उच्च तनाव सेवा) उपभोक्ता। एसईआरसी ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सभी श्रेणियों का टैरिफ तय कर दिया।

मौजूदा टैरिफ के साथ एचटीएस-। उपभोक्ताओं के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को 2004 टैरिफ अनुसूची की तालिका 5.28 और 5.29 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करेगा कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के पहलू पर एसईआरसी द्वारा विधिवत विचार किया गया था। इसे प्रदर्शित करने के लिए, हम यहां नीचे दी गई दो तालिकाओं को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

5.28 एच.टी.सी ॥ उपभोक्तओं के लिए टैरिफ (मौजूदा/प्रस्तावित)

विवरण	टैरिफ
-------	-------

मांग शुल्क

	मौजूदा	प्रस्तावित
रू/केवीए/माह	115	200

ऊर्जा प्रभार

रू/किलोवाट	मौजूदा	प्रस्तावित
समस्त उपभोग	1.72	4.30

ईंधन अधिभार शुल्क

रू/किलोवाट	मौजूदा	प्रस्तावित
	2.44	-

वार्षिक न्यूनतम गारंटी (एएमजी) शुल्क

	<p>इस श्रेणी के लिए न्यूनतम अधीन निम्न लिखित एएमजी अनुबंध शुल्क की मांग के अधीन उस महीने की वास्तविक अधिकतम मांग के आधार पर उचित टैरिफ के अनुसार मासिक न्यूनतम मांग शुल्क या अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो</p>	<p>उपभोक्ता से उचित टैरिफ के अनुसार शुल्क वसुला जायेगा एचटीएस एचटीएस शुल्क की दर पर अनुबंध मांग पर 30 प्रतिशत के लोड फैक्टर और पॉवर फैक्टर 0.9 के आधार पर एएमजी चार्ज</p>
--	--	---

	<p>ऊर्जा शुल्क 30 प्रतिशत के लोड फैक्टर और पॉवर फैक्टर 0.85 के आधार पर अनुबंधित मांग पर रूपये 1.72/केडब्ल्यूएच की</p>	
--	---	--

	दर से दय	
--	----------	--

5.29 ईएचटीएस उपभोक्तओं के लिए टैरिफ (मौजूदा/प्रस्तावित)

विवरण	टैरिफ
-------	-------

मांग शुल्क

	मौजूदा	प्रस्तावित
रू/केवीए/माह	110	200

ऊर्जा प्रभार

रू/किलोवाट	मौजूदा	प्रस्तावित
समस्त उपभोग	4.13	4.15

ईंधन अधिशुल्क

रू/किलोवाट	2.44-	
------------	-------	--

वार्षिक न्यूनतम गारंटी (एएमजी) शुल्क

	इस श्रेणी के लिए न्यूनतम अनुबंध मंग के अधीन, उस महीने की वास्तविक अधिकतम मांग के आधार पर	उचित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता से निम्नलिखित एएमजी शुल्क वसुला जायेगा ऊर्जा की दर पर देय
--	--	---

	उचित टैरिफ के अनुसार मासिक न्यूनतम मांग शुल्क या अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो,	अनुबंध मांग पर 50 प्रतिशत के लोड फैक्टर और पॉवर फैक्टर 0.9 के आधार पर एएमजी चार्ज
--	---	---

	ऊर्जा शुल्क 50 प्रतिशत के लोड फैक्टर और पॉवर फैक्टर 0.85 के आधार पर अनुबंधित मांग पर रूपये 1.69/केडब्ल्यूएच की दर से दय	ईएचटीएच श्रेणी पर लागू शुल्क
--	---	---------------------------------

14. टैरिफ आदेश से पता चलता है कि एसईआरसी ने जेएसईबी के प्रस्ताव की तुलना भारत के अन्य राज्यों में प्रचलित टैरिफ से भी की थी और उसके विस्तृत विश्लेषण के बाद, उसने एचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी, जिसका उल्लेख 2004 टैरिफ अनुसूची की तालिका 5.31 में किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एसईआरसी न्यूनतम गारंटी शुल्क से संबंधित खंड से अनभिज्ञ था, जो

जेएसईबी अपने उपभोक्ताओं से उनके साथ किए गए पहले के समझौतों के अनुसार वसूल रहा था। 2004 टैरिफ अनुसूची में निम्नलिखित चर्चा से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जिसमें एससीआरसी ने एचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को संशोधित और अनुमोदित करने के लिए विशिष्ट कारण दिए हैं।

एसईआरसी ने इन अपीलों पर अपनी प्रतिक्रिया दायर की है, जिसमें इस संबंध में प्रावधान को नीचे दिए गए तरीके से समझाया गया है: "उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि न्यूनतम शुल्क के प्रति कोई आम दृष्टिकोण नहीं है। हालांकि, अगर हम पड़ोसी राज्यों की तुलना करते हैं जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश (132 केवीए से कम पर आपूर्ति) के लिए कोई न्यूनतम शुल्क नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आयोग आदर्श रूप से इस शुल्क को समाप्त करना चाहेगा, लेकिन चालू वर्ष के लिए उसने जानकारी के अभाव के कारण इस शुल्क को बरकरार रखा है। और इस आरोप के वास्तविक प्रभाव का पता लगाने के लिए डेटा। आयोग ने पहले ही बोर्ड को अगली याचिका में इस संबंध में विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है।

चालू वर्ष के लिए, आयोग न्यूनतम शुल्क के कारण उद्योगों पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहेगा और इसलिए इसे मौजूदा स्तर पर रखने का प्रयास

किया गया है। आयोग ने आपूर्ति का न्यूनतम स्तर और उपभोग का न्यूनतम स्तर माना है।

इसके लिए, आयोग ने एक दिन में दो (2) घंटे की औसत खपत को ध्यान में रखते हुए HTS-I और HTS-II श्रेणियों के लिए 10% लोड फैक्टर पर विचार किया है। ईएचटीएस और एचटी के लिए एक दिन में क्रमशः चार (4) घंटे और सात (7) घंटे की औसत खपत पर विचार करके क्रमशः 20% और 30% का विशेष लोड फैक्टर लिया गया है। आयोग का मानना है कि यदि इन श्रेणियों के उद्योग इस न्यूनतम लोड फैक्टर को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें अपने अनुबंधित लोड को कम करना चाहिए। आयोग स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहता है कि यदि खपत उल्लिखित लोड फैक्टर से अधिक है, तो कोई न्यूनतम शुल्क लागू नहीं होगा।

खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने सभी उद्योगों के उपभोक्ताओं के लिए लोड फैक्टर छूट भी शुरू की है। इस परिभाषित लोड फैक्टर से अधिक की संपूर्ण खपत के लिए, ऐसी अतिरिक्त खपत के लिए ऊर्जा शुल्क पर छूट प्रदान की जाती है। आयोग चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति की लागत के अनुरूप टैरिफ संरचना को संरेखित करना चाहता था, लेकिन भारी टैरिफ झटके के कारण यह बाधित हो गया था, जो कि अन्य उपभोगों के लिए अनुवादित होगा और परिणामी वृद्धि जो अन्य के लिए टैरिफ में आवश्यक होगी। श्रेणियाँ। इस प्रकार एक सिद्धांत के रूप में आयोग ने

टैरिफ संरचना में इस विकृति को कम करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। आयोग इस तथ्य से अवगत है कि झारखंड में एचटी उद्योग ने अतीत में क्रॉस सब्सिडी का खामियाजा उठाया है और उन पर लागू टैरिफ आपूर्ति की लागत से ऊपर है। हालाँकि, इस कदम के महत्व को मात्रात्मक गिरावट से नहीं आंका जाना चाहिए बल्कि उस संकेत और इरादे से आंका जाना चाहिए जिसके तहत आयोग भविष्य में टैरिफ को और तर्कसंगत बनाने का इरादा रखता है।

15. हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि हम उन पैराग्राफों में की गई टिप्पणियों से सहमत हैं:

.....10. हम केवल डिमांड चार्ज के बारे में चिंतित हैं, बल्कि कहें तो डिमांड चार्ज के बारे में चिंतित नहीं हैं, लेकिन उपभोक्ता द्वारा डिमांड चार्ज वसूलने के खिलाफ मांग बढ़ाने के उद्देश्य से डिमांड चार्ज की गणना करने के तरीके को टैरिफ में अनुमति दी गई है। ऑर्डर 2003-04 @ 140/- रु. जैसा कि टैरिफ ऑर्डर के पृष्ठ 141 पर उल्लिखित है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि 1993 के टैरिफ के साथ-साथ अनुबंध में क्लॉज 15.2 में एक फॉर्मूला दिया गया था जिसके आधार पर बोर्ड वास्तविक खपत इकाइयों के आधार पर डिमांड चार्ज वसूल रहा था, लेकिन बिजली की इकाइयों की खपत के बावजूद उक्त राशि वसूल रहा था। अब प्रतिवादी-

रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि वे केवल खपत की गई इकाइयों के अनुसार ही उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा और सूत्र के अनुसार नहीं। हमने तालिका 5.27 में निहित बोर्ड के प्रस्ताव से पाया कि बिजली बोर्ड ने जानबूझकर (या अनजाने में) अपना प्रस्ताव केवल इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजूदा वार्षिक मांग शुल्क रु। 125/- प्रति केवीए प्रति माह। बोर्ड के इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और अंततः 2003-04 के टैरिफ आदेश द्वारा डिमांड चार्ज की अनुमति दी गई, जिसका उल्लेख पृष्ठ 141 पर किया गया है, जिसके द्वारा केवल यह अनुमोदित किया गया है कि बिजली बोर्ड रुपये चार्ज करने का हकदार होगा। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 140/- प्रति केवीए प्रति माह, 2003-04 के टैरिफ आदेश ने इसे बढ़ाकर रु. मात्र 140/-.

11. उपरोक्त कारणों को देखते हुए, हम यह नहीं मान सकते कि विद्युत नियामक आयोग ने डिमांड चार्ज के उनके दावे और इसे चार्ज करने के तरीके के संबंध में बिजली बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है....

12. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता-बोर्ड खंड 5.1 की मदद नहीं ले सकता है। जिसमें विद्युत नियामक आयोग ने यह देखा है कि कुछ मामलों का निपटारा नहीं किया गया है और वे वैसे ही बने रहेंगे जैसे वे राज्य में अस्तित्व में थे क्योंकि बिजली बोर्ड द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव दिया गया है। डिमांड चार्ज के साथ-

साथ जिस तरीके से इसे चार्ज किया जाएगा, इस प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने विचार किया और उसके बाद टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया गया है...

16. मामले को विवाद से परे रखने के लिए, हम एक और तथ्य को उजागर करना चाहेंगे, अर्थात् जेएसईबी ने एसईआरसी के समक्ष स्पष्टीकरण आवेदन भी दायर किया था जिसमें कहा गया था कि एचटी-आई के साथ समझौते के खंड 4 (सी) के संबंध में उपभोक्ताओं के लिए, अधिकतम मांग शुल्क समझौते के खंड 4(सी) के तहत निर्धारित होगा। इन आवेदनों को आयोग द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। उन आदेशों को चुनौती देने वाली जेएसईबी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इसलिए, अब जेएसईबी के लिए यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के इस पहलू को एसईआरसी द्वारा 2004 टैरिफ अनुसूची में नहीं निपटाया गया है।

3. पुनः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 का प्रभाव।

विद्युत अधिनियम की धारा 185(2)(ए) और सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6(बी) पर आधारित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा की दलील यह थी कि उपरोक्त प्रावधान के आधार पर 1994 का पूर्व समझौता, बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच दर्ज इसकी धारा 4(सी) सहित बचा लिया गया। अधिनियम की धारा 185(2)(ए) इस प्रकार है:

कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई या की जाने वाली कथित कार्रवाई जिसमें कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या नोटिस बनाया या जारी किया गया या कोई नियुक्ति, पुष्टि या घोषणा की गई या कोई लाइसेंस, अनुमति, प्राधिकरण या छूट दी गई या कोई दस्तावेज या निरस्त कानूनों के तहत निष्पादित दस्तावेज या दिए गए किसी भी निर्देश को, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया या लिया गया माना जाएगा।

हम नीचे सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6(बी) को भी पुनः प्रस्तुत करते हैं: इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन या उसके अंतर्गत विधिवत किए गए या भुगते गए किसी कार्य को प्रभावित करना; या

17. यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि पिछले अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत किए गए या किए गए सभी कार्यों को सहेजा गया है, प्रश्न में समझौता जो वैधानिक शक्ति के प्रयोग में विद्युत बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया था और कानूनी था बल, उपरोक्त प्रावधानों के तहत बचा लिया गया था। इस दलील का समर्थन करने के लिए, श्री सिन्हा ने इस मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और अन्य बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य

विद्युत बोर्ड, इस दलील के साथ कि उपरोक्त निर्णय में इसी पहलू को विशेष रूप से निपटाया गया था और इसलिए यह मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि उस मामले में अदालतों ने विशेष रूप से अधिनियम, 2003 की धारा 185 में निहित निरस्त प्रावधान के प्रभाव को सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 (बी) के साथ पढ़ा और माना कि पिछले समझौतों को तब तक बचाया गया था जब तक कि यह बताया जा सकता है कि उन्हें नष्ट करने का स्पष्ट इरादा था। उन्होंने इस मामले में पहले के फैसले के निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया पंजाब राज्य बनाम. मोहर सिंह, जिसे उपरोक्त निर्णय में उद्धृत किया गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

जब भी किसी अधिनियम को निरस्त किया जाता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित परिणाम तब तक होंगे जब तक, जैसा कि धारा स्वयं कहती है, एक अलग इरादा प्रकट नहीं होता है। एक साधारणनिरसन के मामले में विपरीत राय की अभिव्यक्ति के लिए शायद ही कोई जगह होती है। लेकिन जब उसी विषय पर नए कानून को निरस्त करने के बाद हमें निस्संदेह नए अधिनियम के प्रावधानों को देखना होगा, लेकिन केवल यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या वे एक अलग इरादे का संकेत देते हैं। जांच का विषय यह नहीं होगा कि नया अधिनियम स्पष्ट रूप से पुराने अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखता है या नहीं, बल्कि क्या यह उन्हें नष्ट करने का इरादा प्रकट करता है। इसलिए हम इस

व्यापक प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सकते कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को तब खारिज कर दिया जाता है जब किसी अधिनियम को निरस्त करने के बाद नया कानून बनाया जाता है। धारा 6 ऐसे मामलों में भी लागू होगी जब तक कि नया कानून धारा के प्रावधानों के साथ असंगत या इसके विपरीत कोई इरादा प्रकट न करे। इस तरह की असंगति को नए कानून के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करके सुनिश्चित करना होगा और बचत खंड की अनुपस्थिति ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। इन सिद्धांतों के आलोक में अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

(रेखांकित करना हमारा है)

उन्होंने उक्त निर्णय में निम्नलिखित चर्चा पर भी भरोसा किया:

हमने उपरोक्त पैराग्राफों का उल्लेख किया है क्योंकि श्री गुप्ता ने तर्क दिया है कि जब किसी अधिनियम को निरस्त किया जाता है और नए कानून का प्रतिस्थापन होता है, तो आमतौर पर एक मंच का निहित अधिकार नष्ट हो जाता है। 2003 अधिनियम की धारा 185 को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर, इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि भले ही सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 लागू होगी, फिर भी यह अपील के मंच को नहीं बचाती है। मैं कोई विपरीत इरादा नहीं लगता कि सामान्य धारा अधिनियम के 6 लागू नहीं होंगे। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए

कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अनुसार क्या अधिकार है और क्या नहीं है, के बीच का अंतर अक्सर बहुत उपयुक्त होता है। किसी कानून के निरस्त होने से जो अप्रभावित रहता है, वह इसके तहत प्राप्त या उपार्जित अधिकार है, न कि अधिकार प्राप्त करने की केवल आशा, या उम्मीद, या इसके लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता (देखें)

एमएस शिवानंद बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य,

18. इस तर्क की सराहना करने के लिए, हमें उपभोक्ताओं के साथ किए गए 1994 के समझौते के कुछ प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना होगा। ये एचटी समझौते के पैरा 4(सी) और 11 हैं:

4. (सी) किसी भी महीने में आपूर्ति के लिए अधिकतम मांग शुल्क अनुबंध मांग के 75% महीने के लिए अधिकतम केवीए मांग पर आधारित होगा, जो कि खंड 13 के प्रावधान के अधीन है....

11. इस समझौते को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के साथ-साथ नियमों, विनियमों (यदि कोई हो) टैरिफ और आपूर्ति के लिए नियम और शर्तों के अधीन पढ़ा और समझा जाएगा। बिजली तैयार की गई और इसके तहत जारी की गई और फिलहाल लागू है जहां तक यह क्रमशः लागू हो सकता है और ऐसे सभी प्रावधान उनके और इस

समझौते के नियमों और शर्तों के बीच किसी भी संघर्ष या असंगतता के मामले में प्रबल होंगे।

19. यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस अवधि के दौरान लागू टैरिफ 2003-04 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश दिनांक 27.12.2003 था जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कानून का बल था। इस प्रकार, उपरोक्त से क्या पता चलता है क्या यह कि भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि पहले किए गए वैधानिक समझौते बच गए थे, विचाराधीन समझौता 2004 टैरिफ अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस समय, हम इस मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना चाहेंगे बीएसईएस लिमिटेड बनाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और अन्य, जिसमें निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गईं।

16. अधिनियम में "टैरिफ" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। "टैरिफ" वाणिज्य का एक कार्टेल है और आम तौर पर यह दरों की एक पुस्तक है। इसका मतलब टैरिफ में निर्दिष्ट श्रेणी या ग्राहकों की श्रेणियों को प्रदान की जाने वाली मानक कीमतों या शुल्कों की एक अनुसूची होगी। धारा 22 की उपधारा (1) स्पष्ट रूप से बताती है कि राज्य आयोग बिजली (थोक, थोक, ग्रिड या खुदरा) और ट्रांसमिशन सुविधाओं के उपयोग के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा। इसके पास वितरण उपयोगिताओं की बिजली खरीद को विनियमित करने की भी शक्ति है, जिसमें वह कीमत

भी शामिल है जिस पर राज्य में पारेषण, बिक्री, वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदी जाएगी। अधिनियम की धारा 2(1) में "उपयोगिता" को परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, बिक्री, वितरण या आपूर्ति, जैसा भी मामला हो, में लगा कोई भी व्यक्ति या इकाई। धारा 29 में कहा गया है कि बिजली के अंतर-राज्य पारेषण के लिए टैरिफ और किसी राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-थोक, थोक या खुदरा-अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा और टैरिफ राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। धारा 29 की उपधारा (2) से पता चलता है कि टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी और ऐसा करते समय, आयोग को उसके खंड (ए) से (जी) में बताए गए कारकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। पहले उल्लिखित विनियमों से पता चलता है कि उत्पादन कंपनियों और उपयोगिताओं को अपने टैरिफ के अनुमोदन के लिए पहले आयोग से संपर्क करना होगा, चाहे वह उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति के लिए और आपूर्ति के नियमों और शर्तों के लिए भी हो। वे अपने ग्राहकों से केवल वही टैरिफ वसूल सकते हैं जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो। आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए टैरिफ को चार्ज करना एक अपराध है जो अधिनियम की धारा 45 के तहत दंडनीय है। अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों से पता चलता है कि आयोग के पास टैरिफ निर्धारित करने की विशेष शक्ति है। आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ अंतिम और बाध्यकारी है

और लाइसेंसधारी, उपयोगिता या किसी अन्य के लिए अलग टैरिफ चार्ज करना स्वीकार्य नहीं है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 पर आधारित तर्क भी इस मामले के परिणामों में कोई बदलाव नहीं लाएगा। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के उस फैसले में कोई गलती नहीं करते जिसके खिलाफ अपील की गई है।

21. इससे पहले कि हम अलग हों, अपीलकर्ता के एक और तर्क से निपटना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिट याचिका दायर करने में देरी हुई थी क्योंकि 1994 के समझौते के खंड 4 (सी) के आधार पर जेएसईबी द्वारा बिल जारी किए गए थे, यहां तक कि 2004 टैरिफ अनुसूची के निर्माण के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था और उन्होंने संपर्क किया था। न्यायालय ने केवल वर्ष 2010 में रिट याचिकाएँ दायर कीं। इस प्रकार, 5 वर्ष की देरी और देरी हुई। आगे तर्क दिया गया है कि ऐसे परिदृश्य में, उच्च न्यायालय को कम से कम अपीलकर्ताओं को पहले की अवधि के लिए उठाए गए बिलों के तहत ली गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। अन्य संबंधित दलील यह थी कि यह उन उपभोक्ताओं के लिए अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा जो बिजली के उपयोगकर्ता से राशि वसूल करेंगे।

22. जहां तक रिट याचिका दायर करने में देरी का सवाल है, घटनाओं के कालक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे विधिवत समझाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कनेक्शन काटने की धमकी के विरोध में उपभोक्ताओं ने जेएसईबी द्वारा बढ़ाए गए बिल की राशि का भुगतान किया था। ऐसा करते समय, उन्होंने जेएसईबी के समक्ष विशेष दलील रखी थी कि अब उसे 2004 टैरिफ अनुसूची के अनुसार बिल जारी करना चाहिए। यह मामला जेएसईबी के स्तर पर विचाराधीन रहा, जो 2004 टैरिफ अनुसूची के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय के साथ-साथ एसईआरसी का दरवाजा खटखटाता रहा। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, स्पष्टीकरण आवेदन दायर किए गए थे जिन्हें आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, चूंकि जेएसईबी ने इन आवेदनों को खारिज करने के बाद भी अपने रुख पर कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए उपभोक्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिकाएं दायर कीं। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से संपर्क करने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

23. अन्याय और संवर्धन की दलील अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। सबसे पहले, ऐसी कोई याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष या तो एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के समक्ष नहीं उठाई गई थी। विशेष अनुमति याचिका में, यह निवेदन वर्तमान अपीलों की सुनवाई के समय पहली बार किया गया था। इसके अलावा, यह कर के भुगतान का मामला

नहीं है जो उपभोक्ताओं पर डाला गया बोझ है। केवल ऐसे मामलों में ही रोक लगाई गई थी मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य, कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का प्रश्न विचार हेतु उठेगा। जहां तक वर्तमान जैसे मुद्दे का सवाल है, उपरोक्त निर्णय के पैरा 107 में ऐसा प्रश्न खुला छोड़ दिया गया था। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्यायपूर्ण संवर्धन की अवधारणा का करों के अलावा रिफंड के लिए कोई उपयोग नहीं है, जैसा कि उसे पढ़ने से स्पष्ट है।

107. एक स्पष्टीकरण: कैप्टिव उपभोग के मामले में स्थिति पर हमारे द्वारा इस राय में विचार नहीं किया गया है। हम उस प्रश्न को खुला छोड़ते हैं।

24. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं.

डी.जी. याचिकाएं खारिज कर दी गई ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारीनीरजादाधीचअपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02 किशनगढ (UID RJ00438) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।